

प्रेषक,

शैलेश बगौली,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पर्यटन निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 7 जनवरी, 2016

विषय:- गढ़ी कैन्ट देहरादून में स्थित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय भवन परिसर में पर्यटन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-524 / VI(1) / 2015-02(19) / 2011, दिनांक 31 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या-1866 / VI(1) / 2015-02(19) / 2011, दिनांक 7 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत योजना हेतु ₹ 561.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 10.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

उक्त के संदर्भ में आपके पत्र संख्या-449 / 2-6-650 / 2015, दिनांक 1 जनवरी, 2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'पर्यटन परिषद के लिए आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण' मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 110.00 लाख में से प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त धनराशि ₹ 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) उपरोक्त योजना की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
- (ii) स्वीकृत धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा एक मुश्त जारी न करते हुए दो चरणों में आहरित कर नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार जारी किया जायेगा। द्वितीय किस्त को प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- (iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iv) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।
- (v) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का मृदा परीक्षण एवं भू-गर्भीय परीक्षण अनिवार्य रूप करा लिया जाय।
- (vi) कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रदर्शिका, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा डी0एस0आर0 के नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी मद में फाईनेंशियल ड्रुप्लीकेसी न हो।
- (vii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (viii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (ix) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- (x) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (xi) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा इसके क्रम में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (xii) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (xiv) वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (xv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047 / XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (xvi) कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाशीर्षक 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-संबर्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर-02-पर्यटन परिषद के लिये आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या-1336/XXVII(1)/2015, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी-S.L.G.O.12.G.O.107..द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या:- 30 / VI(1) / 2016-02(19) / 2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
- 6- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाईल।

अज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव।